

धींधवाल 50-50

एकजाम रिव्यू

राजस्थान की राजव्यवस्था

राज्य में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी पुस्तक

RAS, CET, कॉलेज व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता, शिक्षक ग्रेड-II, शिक्षक ग्रेड-III, REET, H.M., पुलिस उपनिरीक्षक, पटवार, ग्रामसेवक, सहायक कारापाल, जेलर प्रहरी, महिला पर्यवेक्षक, कृषि पर्यवेक्षक, पशुधन सहायक, पुस्कालयाध्यक्ष, संगणक, पुलिस कानिस्टेबल, वनपाल, वनरक्षक, स्टेनोग्राफर, लेब असिस्टेंट, PTI, JEN Civil, राजस्थान हाइकोर्ट LDC आदि परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न।

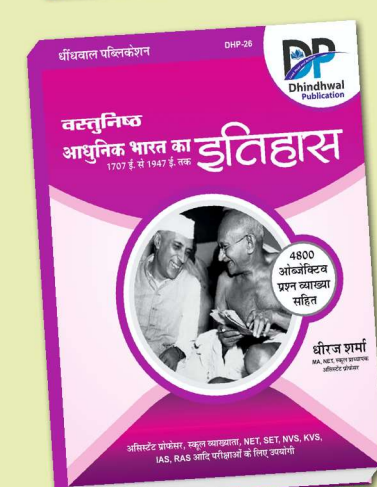
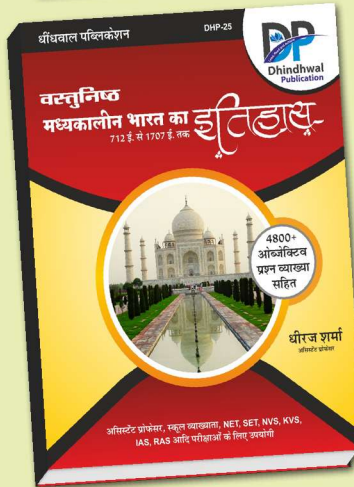
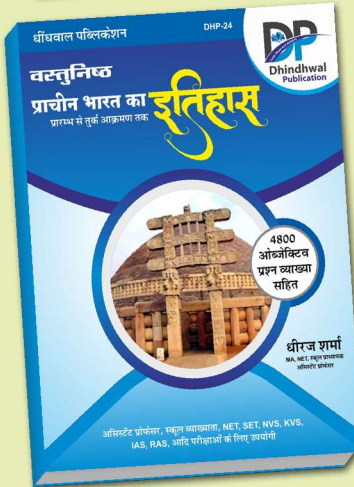
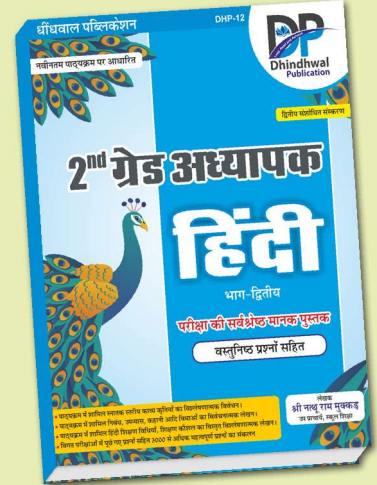
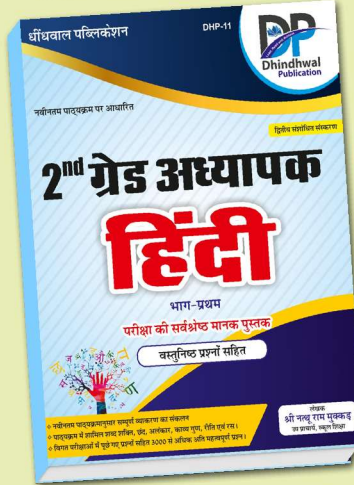
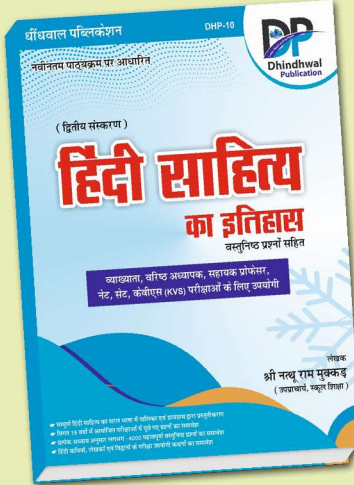
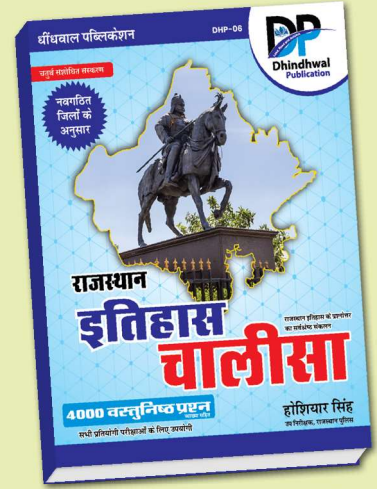
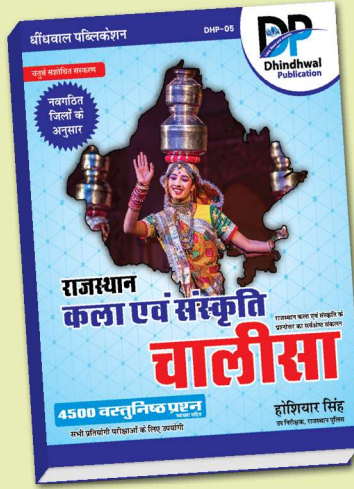
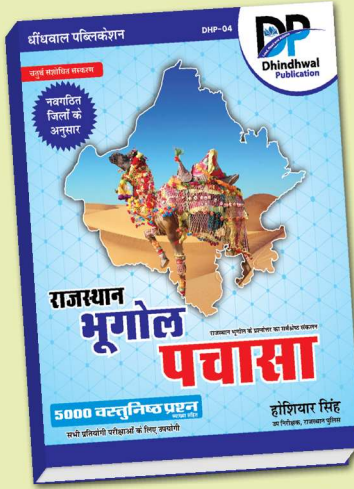


सभी आवश्यक
प्रश्नों की
व्याख्या सहित



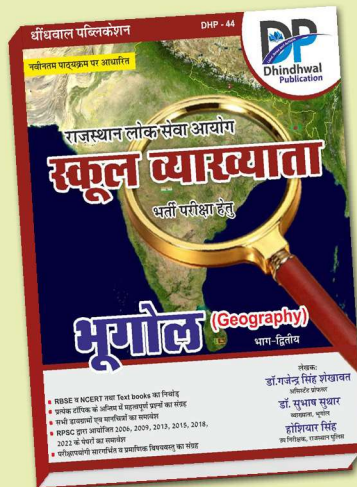
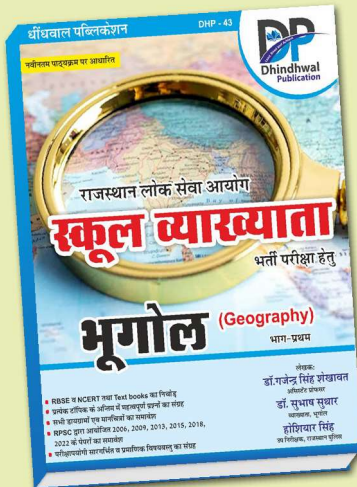
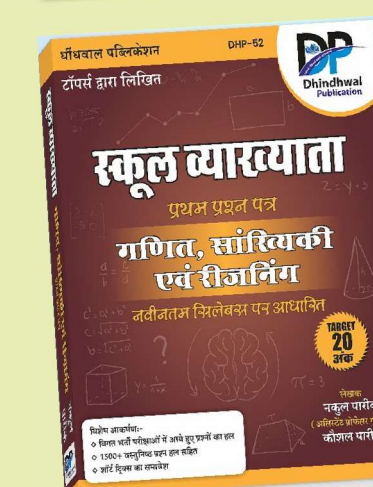
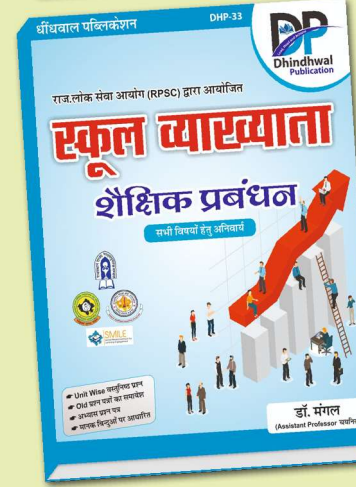
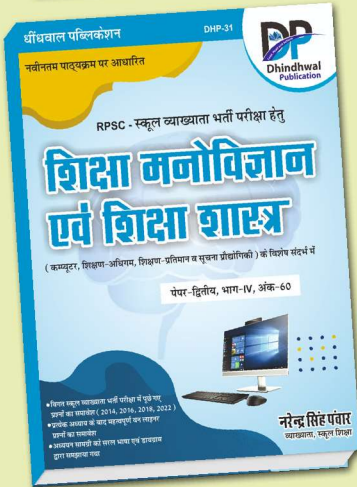
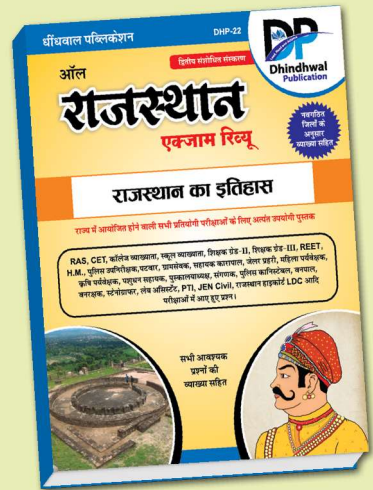
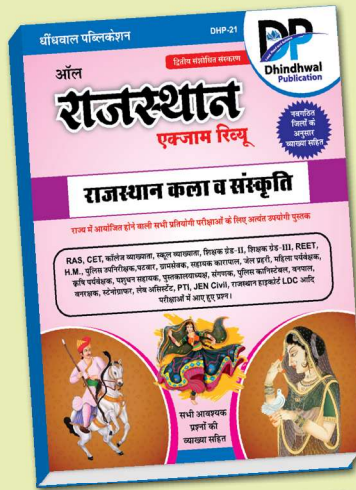
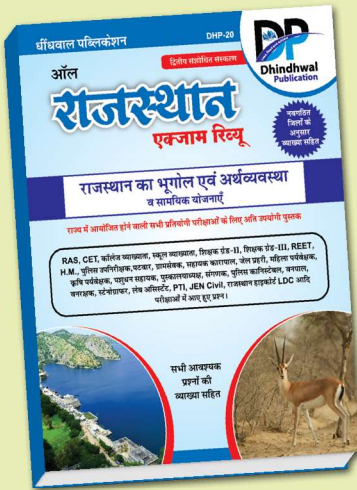
परीक्षा में सफलता हेतु इन पुस्तकों का अध्ययन करें

हमारे प्रकाशन की अन्य पुस्तकें



परीक्षा में सफलता हेतु इन पुस्तकों का अध्ययन करें

हमारे प्रकाशन की अन्य पुस्तकें





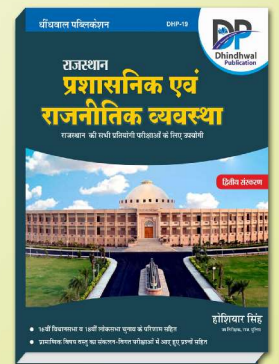
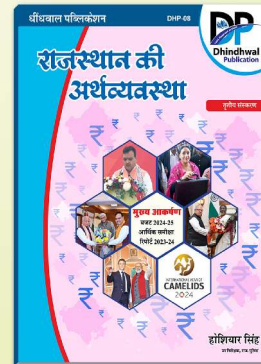
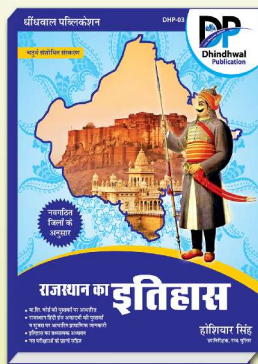
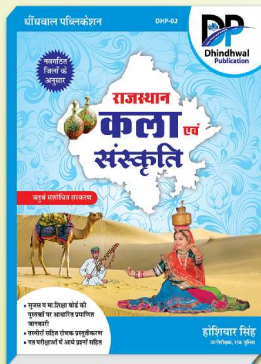
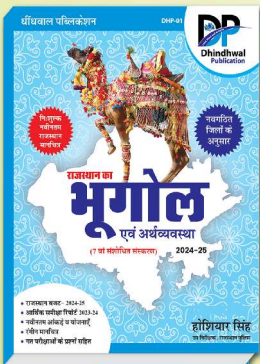
होशियार सिंह

उप निरीक्षक, राज. पुलिस

: लेखक परिचय :

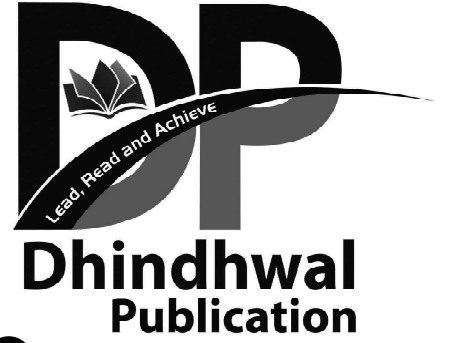
होशियार सिंह का जन्म ग्राम रतनपुरा तहसील राजगढ़ जिला चुरू (राजस्थान) में हुआ। आपने स्नातक करने के दौरान ही वर्ष 2003 से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आरम्भ की, राजस्थान पुलिस (जिला बीकानेर वर्ष 2008) में कानिस्टेबल के पद पर चयन के साथ ही 2008 में तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर चयन हुआ। आपने 5 वर्ष तक जिला राजसमंद में तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएँ दी, तत्पश्चात् द्वितीय श्रेणी शिक्षक (हिन्दी) 2013 में चयन होने पर आपने राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कतरियासर (बीकानेर) में अपनी सेवाएँ दी, तत्पश्चात् राजस्थान पुलिस उपनिरीक्षक 2014 में चयन हुआ, वर्तमान में आप राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक हैं, आपको राजस्थान की विभिन्न प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में अध्यापन व मार्गदर्शन का गहन अनुभव है।

लेखक की अन्य पुस्तकें



धींधवाल पब्लिकेशन

प्रस्तुत करते हैं-



धींधवाल 50-50

एकजाम रिव्यू

राजस्थान की राजव्यवस्था

- ☞ प्रश्नों की व्याख्या में हिन्दी ग्रन्थ अकादमी की पुस्तकों व विभिन्न मूल अधिनियमों से प्रामाणिक तथ्यों का समावेश।
- ☞ वर्ष 2011 से वर्ष 2024 तक की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का संकलन।

RAS, कॉलेज व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता, शिक्षक IInd ग्रेड, शिक्षक IIIrd ग्रेड, REET, H.M., CET, पुलिस उपनिरीक्षक, पटवार, ग्रामसेवक, राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल, राजस्थान हाइकोर्ट, वनरक्षक, वनपाल, पुस्तकालयाध्यक्ष, PTI IInd ग्रेड, PTI IIIrd ग्रेड व राजस्थान की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी पुस्तक।

धींधवाल पब्लिकेशन

B-22, वैष्णो विहार, बीकानेर

मो.- 8306733800

संकलनकर्ता:-होशियार सिंह

(उप निरीक्षक, राजस्थान पुलिस)

प्रकाशक:-

धींधवाल पब्लिकेशन

B-22, वैष्णो विहार, बीकानेर

मो.- 8306733800

 - Dhindhwal Publication

 - धींधवाल पब्लिकेशन

 - Dhindhwal Classes

 - @Publication-DP

 - Dhindhwal Publication

बुक कोड-DHP-23

संस्करण- 2024-25

© सर्वाधिकार- लेखक

फिक्स रेट- 85 रुपये

मुद्रक-

पिंकसिटी ऑफसेट, जयपुर

इस पुस्तक के किसी भी अंश का लेखक तथा प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना मुद्रित करना, कराना तथा इस पुस्तक की व इस पुस्तक के किसी भाग की फोटोकॉपी, स्कैनिंग, इलेक्ट्रोस्टेट, मशीनी टंकण अथवा किसी भी तरीके से पुनः उपयोग करना, पी.डी.एफ बनाकर वाट्सअप, टेलीग्राम व फेसबुक आदि पर प्रसारित करना पूर्णतः वर्जित है।

इस पुस्तक को तैयार करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है पुस्तक में दिये गये तथ्य व विवरण उचित व विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त किये गये हैं, फिर भी इसमें किसी त्रुटि, गलती, कमी अथवा लोप रह जाना संभव है। अतः ऐसी किसी भी त्रुटि, गलती, कमी अथवा लोप के कारण हुई क्षति अथवा क्लेश के लिए लेखक, प्रकाशक, सम्पादक, मुद्रक, विक्रेता व कर्मचारीगण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। आप उपर्युक्त सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए स्वेच्छा से पुस्तक खरीद रहे हैं अतः दायित्व आपका स्वयं का होगा। सभी प्रकार के परिवादों का न्यायिक क्षेत्र बीकानेर होगा।

भूमिका

प्रिय परीक्षार्थियों,

मुझे 'राजस्थान की राजव्यवस्था' की 'एकजाम रिव्यू' पुस्तक का प्रथम संस्करण आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है। इससे पूर्व 'राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था', 'राजस्थान की कला व संस्कृति', 'राजस्थान का इतिहास' तथा 'राजस्थान प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था' सहित हमारी सभी पुस्तकें पूरे राजस्थान में पसन्द की जा रही हैं।

प्रस्तुत पुस्तक में राजस्थान की राजव्यवस्था के वर्ष 2011 से 2024 तक की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को शामिल किया गया है। इस पुस्तक में सुजस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्यपुस्तकों व हिन्दी ग्रन्थ अकादमी की पुस्तकों के तथ्यों को शामिल करते हुए प्रश्नों की विस्तार से व्याख्या दी गई है।

प्रस्तुत पुस्तक मैंने हमारी अन्य पुस्तकों (राजस्थान G.K.) को पढ़ रहे परीक्षार्थियों की माँग पर तैयार की है, मेरा पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान की राजव्यवस्था एकजाम रिव्यू की यह पुस्तक आपकी तैयारी में मील का पत्थर साबित होगी। हमने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए प्रश्नों के उत्तर उनकी व्याख्या के साथ दिए हैं, साथ ही व्याख्या लिखते हुए इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि उस प्रश्न से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छोटे नहीं।

इस पुस्तक से आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं के पैटर्न को समझने में आसानी होगी। इस विषय में अपनी तैयारी को परखने के साथ-साथ राजव्यवस्था के प्रत्येक टॉपिक की गहरी समझ भी विकसित होगी। पुस्तक को परीक्षार्थियों की आकांक्षाओं के अनुरूप अधिक से अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है। व्याख्या की भाषा सरल व शैली बोधगम्य रखी गयी है।

मैं उन सभी मित्रों, प्रतियोगी छात्रों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस पुस्तक के लेखन हेतु ऊर्जावान प्रेरणा दी। यह पुस्तक मैं अपनी स्वर्गीया माताजी को समर्पित करता हूँ। पुस्तक लेखन के कार्य में मेरी धर्मपत्नी श्रीमती विमला का विशेष सहयोग रहा। मैं अपने सहयोगियों दिनेश कूकणा, मनीराम मूण्ड, मुकेश कुमावत, लालचन्द जाट, विक्रम सिंह, धर्मेन्द्र बिशु, कानाराम वर्मा व टाइपिस्ट विष्णु पुरी, असलम अली, मोहम्मद रफीक व यशवंत प्रजापत का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके अथक परिश्रम से पुस्तक को तैयार करना संभव हो पाया।

यद्यपि पुस्तक के लेखन एवं प्रकाशन में पूर्ण सावधानी बरती गई है, तथापि आगामी संस्करणों में इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिए आपके अमूल्य सुझावों (मो. 8306733800) का हार्दिक स्वागत है।

“परिंदों से भी ऊँची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी...

चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी...!!

होशियार सिंह

(उप निरीक्षक, राजस्थान पुलिस)

विषय-सूची



क्र.सं.	विषय-सूची	पृष्ठ संख्या
1.	राज्यपाल	1-18
2.	मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्रिपरिषद्	19-31
3.	राज्य विधानमण्डल	32-42
4.	राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं नियम	43-46
5.	संसद में राजस्थान	47-48
6.	उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय	49-54
7.	राज्य सचिवालय व मुख्य सचिव	55-59
8.	संभाग व जिला प्रशासन व्यवस्था	60-62
9.	पंचायती राज	63-80
10.	नगरीय स्वशासन	81-87
11.	प्रमुख आयोग	88-113
A	राजस्थान लोक सेवा आयोग	88-93
B	राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग	94-100
C	राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग	101-103
D	राजस्थान राज्य वित्त आयोग	103-104
E	राजस्थान राज्य महिला आयोग	105
F	राजस्थान राज्य सूचना आयोग	106-108
G	लोकायुक्त	109-112
H	राज्य का महाधिवक्ता	113
12.	प्रमुख अधिनियम	114-116
A	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005	114-115
B	राजस्थान लोक सेवा गारन्टी अधिनियम-2011	115-116
C	राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम-2012	116

1

राज्यपाल

1. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है?

- (1) अनुच्छेद 157 (2) अनुच्छेद 159
(3) अनुच्छेद 153 (4) अनुच्छेद 155

(CET 10 + 2 (Shift-6)-2024)

व्याख्या—(4) राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय मंत्री परिषद् की सलाह से की जाती है।

2. राजस्थान के राज्यपाल के नामों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें (CET 10 + 2 (Shift-4)-2024)

- a. श्री रघुकुल तिलक b. श्री सुखदेव प्रसाद
c. डॉ. सम्पूर्णानंद d. डॉ. एम. चेन्ना रेड्डी
- नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें
- (1) b, c, a, d (2) c, b, d, a
(3) c, a, b, d (4) a, b, c, d

व्याख्या—(3) डॉ. सम्पूर्णानंद (1962 से 1967), श्री रघुकुल तिलक (1977 से 1981), श्री सुखदेव प्रसाद (1988 से 1989), डॉ. एम. चेन्ना रेड्डी (1992 से 1993)

3. राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें) (CET 10 + 2 (Shift-4)-2024)

- (1) महाराजा सवाई मानसिंह (2) श्री गुरुमुख निहाल सिंह
(3) श्री हेम बहादुर सिंह (4) श्री कलराज मिश्र

उत्तर—(2)

4. राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ और कार्य हैं—

- a. राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाहियाँ औपचारिक रूप से उनके नाम पर की जाती हैं।
b. वह राज्य के प्रशासन से सम्बन्धित कोई भी जानकारी तथा कानून के प्रस्ताव के बारे में मंत्रियों से जानकारी नहीं मांग सकते हैं।
c. वह राज्य सरकार के कामकाज के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बना सकते हैं।
d. वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं।
- नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें:
- (1) केवल a, b और d (2) केवल b, c और d
(3) केवल a, c और d (4) केवल b, a और c

(CET 10 + 2 (Shift-3)-2024)

व्याख्या—(3) अनुच्छेद-167(क) के अनुसार राज्यपाल राज्य के प्रशासन से सम्बन्धित कोई भी जानकारी तथा कानून के प्रस्ताव के बारे में मुख्यमंत्री से जानकारी मांग सकते हैं।

5. निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? (CET 10 + 2 (Shift-2)-2024)
निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें।

- (1) राज्य निर्वाचन आयोग
(2) राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
(3) राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति
(4) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

व्याख्या—(4) राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

6. राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? (निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें)

- (1) मुख्यमंत्री (2) राष्ट्रपति
(3) प्रधानमंत्री (4) भारत के मुख्य न्यायाधीश
- (CET 10 + 2 (Shift-1)-2024)

व्याख्या—(2) राज्यपाल को हटाने के आधार तथा प्रक्रिया का संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन सामान्यतः राज्यपाल को राष्ट्रपति पद से हटा सकता है। राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण करता है।

7. निम्नलिखित में से प्रायः कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है?

- (1) राज्यपाल (2) प्रधानमंत्री
(3) शिक्षा मंत्री (4) मुख्यमंत्री

(CET Graduation (Shift-2)-2024)

व्याख्या—(1) राज्यपाल, राज्य के सभी राज्य विश्वविद्यालयों (राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित) का कुलाधिपति होता है तथा इनके कुलपतियों की नियुक्तियाँ भी करता है।

8. जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल घोषित किया जाता है। यह किस अनुच्छेद से होता है? (CET Graduation (Shift-4)-2024)

- (1) अनुच्छेद 360 (2) अनुच्छेद 350
(3) अनुच्छेद 352 (4) अनुच्छेद 356

133. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

- (1) अनुच्छेद : 154—राज्य की कार्यपालक शक्तियाँ
 (2) अनुच्छेद : 155— राज्यपाल की नियुक्ति
 (3) अनुच्छेद : 156— राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएँ
 (4) अनुच्छेद : 163— राज्य मंत्री परिषद

(ग्राम सेवक— 2016)

व्याख्या—(3) अनुच्छेद 156— राज्यपाल का कार्यकाल/पदावधि।

134. नीचे दिए हुए दो वक्तव्यों पर विचार कीजिये—

कथन (A) : राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छापर्यंत ही रहता है।

कारण (R) : राज्यपाल की नियुक्ति प्रधान मंत्री द्वारा होती है।

ऊपर के दोनों वक्तव्यों के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है ?

- (1) A और R दोनों सही हैं तथा A की सही व्याख्या R करता है।
 (2) A और R दोनों सही हैं पर A की सही व्याख्या R नहीं करता।
 (3) A सही है पर R गलत है।
 (4) A गलत है पर R सही है।

(ग्राम सेवक— 2016)

व्याख्या—(3) राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

135. राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से किसने अपने पद से त्यागपत्र दिया था? (jr. accountant- 2016)

- (1) जोगिंदर सिंह (2) बलीराम भगत
 (3) मदन लाल खुराना (4) अंशुमान सिंह

व्याख्या—(डिलीट) उक्त प्रश्न में दो विकल्प सही है। इस कारण इस प्रश्न को डिलीट किया गया, क्योंकि श्री जोगिन्दर सिंह ने उत्तर प्रदेश के लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए राज्यपाल के पद से त्याग पत्र दे दिया तथा श्री मदनलाल खुराना ने अपने निजी कारणों से राज्यपाल के पद से त्याग पत्र दे दिया था।

136. एक राज्य के राज्यपाल के सन्दर्भ में निम्न कथनों में कौन से सही है? (पटवार— 2016)

- (A) राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ इसमें निहित हैं।
 (B) इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
 (C) वह अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं।
 (D) इनकी बरखास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित है।
 नीचे दिए हुए कूट के आधार पर सही उत्तर को चुनिए —

- (1) 'A', 'B' एवं 'D' (2) 'A', 'B' एवं 'C'
 (3) 'A', 'C' एवं 'D' (4) 'A', 'B', 'C' एवं 'D'

व्याख्या—(2) राज्यपाल को बर्खास्त करने के कारण संविधान में उल्लेखित नहीं है।

137. राजस्थान राज्य में 30 जून, 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? (RAS Pre.- 2016)

- (1) 5 बार (2) 3 बार
 (3) 6 बार (4) 4 बार

उत्तर—(4)

138. राजस्थान के राज्यपाल के रूप में श्री कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व, निम्नांकित में से कौन राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल थे? (RAS Pre.- 2016)

- (1) ओ.पी. कोहली (2) रामनरेश यादव
 (3) राम नायक (4) मार्गरेट अल्वा

व्याख्या—(3) श्री राम नाईक को 08 अगस्त, 2014 से 03 सितम्बर, 2014 तक राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

139. सही उत्तर चुनें: (RAS Pre.- 2016)

राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं

- (1) सभी राज्य विश्वविद्यालयों के
 (2) सभी राज्य विश्वविद्यालयों तथा राज्य में कार्यरत सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के
 (3) सभी राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के
 (4) सभी राज्य विश्वविद्यालयों, राज्य में स्थित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालयों के

उत्तर—(1)

140. राज्य के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं

- (1) राष्ट्रपति
 (2) उप-राष्ट्रपति
 (3) प्रधानमंत्री
 (4) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

उत्तर—(1) (स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान— 2016)

141. राज्य के गवर्नर की आयु नियुक्ति के समय कम से कम कितनी होनी चाहिए?

- (1) 30 वर्ष (2) 35 वर्ष
 (3) 25 वर्ष (4) 40 वर्ष

उत्तर—(2) (स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान— 2016)

142. राज्य के गवर्नर किसके प्रसाद पर्यन्त पद पर बने रहते हैं? (स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान— 2016)

- (1) मुख्यमंत्री (2) राष्ट्रपति
 (3) उप-राष्ट्रपति (4) प्रधानमंत्री

2

मुख्यमंत्री व राज्य मंत्रिपरिषद्

1. राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? (CET 10 + 2 (Shift-6)-2024)

- (1) विधान सभा अध्यक्ष
(2) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
(3) राज्यपाल
(4) मुख्यमंत्री

उत्तर—(4)

2. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है?

- (1) अनुच्छेद 165 (2) अनुच्छेद 166
(3) अनुच्छेद 163 (4) अनुच्छेद 164

(CET 10 + 2 (Shift-5)-2024)

व्याख्या—(4) अनुच्छेद 164(1)— मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण करेंगे।

3. राजस्थान के वर्तमान (01 सितम्बर, 2024 के दिन) मुख्यमंत्री कौन है? (CET 10 + 2 (Shift-3)-2024)

- (1) भजन लाल शर्मा (2) वसुंधरा राजे
(3) अशोक गहलोत (4) भैरों सिंह शेखावत

व्याख्या—(1) श्री भजनलाल शर्मा पदक्रम के अनुसार राजस्थान के 26वें मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने 15 दिसम्बर, 2023 को शपथ ली।

4. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन करता है?

- (1) अनुच्छेद 162 (2) अनुच्छेद 167
(3) अनुच्छेद 164 (4) अनुच्छेद 165

(CET 10 + 2 (Shift-2)-2024)

व्याख्या—(2) अनुच्छेद 167(क)— मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषय संबंधी मंत्रीपरिषद् के सभी निर्णय राज्यपाल को सूचित करेगा। **अनुच्छेद 167(ख)**— मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन व विधान विषय से संबंधित जानकारीयों के बारे में राज्यपाल द्वारा सूचना माँगे जाने पर सूचना प्रदान करेगा। **अनुच्छेद 167(ग)**— किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय कर लिया है, लेकिन मंत्रीपरिषद् ने विचार नहीं किया है, तब राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मुख्यमंत्री उस विषय को मंत्रीपरिषद् के समक्ष विचार के लिए रखेगा।

5. निम्नलिखित में से कौन, राजस्थान की प्रथम महिला उप-मुख्यमंत्री थी? (CET Graduation (Shift-3)-2024)

- (1) कमला बेनीवाल (2) वसुंधरा राजे
(3) दिया कुमारी (4) प्रतिभा पाटिल

व्याख्या—(1) राजस्थान की पहली महिला उपमुख्यमंत्री कमला बेनीवाल थी। यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय वर्ष 2003 में उपमुख्यमंत्री बनी। राजस्थान की दूसरी महिला उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी है।

6. निम्नलिखित में से कौन-से पद का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है?

- (1) लोकसभा अध्यक्ष (2) प्रधानमंत्री
(3) मुख्यमंत्री (4) उप मुख्यमंत्री

उत्तर—(4) (CET Graduation (Shift-2)-2024)

7. राजस्थान की मंत्रिपरिषद् की न्यूनतम सदस्य-संख्या है—(RAS Pre-2023)(असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत विभाग) 2024)

- (1) 12 (2) 15
(3) 30 (4) 17

व्याख्या—(1)— वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 है। इस प्रकार राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 तथा अधिकतम संख्या 30 हो सकती है।

8. राजस्थान में पूर्व गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद् के स्थान पर किस इंस्टीट्यूट/कौंसिल का गठन किया गया है? (AEN (Mech.)- 2024)

- (1) राजस्थान कौंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स
(2) राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन
(3) राजस्थान इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अफेयर्स कौंसिल
(4) राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अफेयर्स

व्याख्या—(2) मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद् के स्थान पर 'राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन (रीति)' का गठन किया गया है। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। इसमें उपाध्यक्ष व पूर्णकालिक सदस्यों का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जायेगा।

रीति के प्रमुख कार्य— विकसित राजस्थान 2047 का निर्माण तथा नीति-निर्धारण करना व विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के विकास के लिए नीति तैयार कर सुझाव देना।

69. राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोक सभा के सदस्य नहीं रहे हैं? (RAS Pre.- 2021)

- (A) हरिदेव जोशी (B) भैरों सिंह शेखावत
(C) टीकाराम पालीवाल (D) बरकतुल्लाह खान
(1) (A) (B), (C) और (D) (2) केवल (A) और (B)
(3) केवल (B), (C), और (D) (4) केवल (A), (B) और (D)

व्याख्या—(4) वे मुख्यमंत्री जो लोकसभा सदस्य भी रहे—

1. हीरालाल शास्त्री 2. टीकाराम पालीवाल 3. मोहनलाल सुखाड़िया
4. शिवचरण माथुर 5. जगन्नाथ पहाड़िया 6. वसुंधरा राजे
7. अशोक गहलोत

70. निम्नांकित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात् बरकतुल्लाह खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? (SI - 13-9-2021)

- (1) टीका राम पालीवाल (2) मोहनलाल सुखाड़िया
(3) शिवचरण माथुर (4) हरिदेव जोशी

व्याख्या—(2) मार्च 1971 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव के बाद कांग्रेस विधायक दल में बहुमत का समर्थन प्राप्त होने के बावजूद 08 जुलाई, 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी के निर्देश पर मोहनलाल सुखाड़िया ने त्याग पत्र दे दिया।

71. राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की 'कामचलाऊ सरकार' (केयरटेकर गवर्नमेंट) के विरुद्ध विधान सभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था— (SI - 14-9-2021)

- (1) जयनारायण व्यास (2) टीकाराम पालीवाल
(3) मोहनलाल सुखाड़िया (4) हरिदेव जोशी

व्याख्या—(2) टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध पहली बार 1952 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन पारित नहीं हुआ।

72. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? (VDO 27-12-2021)

- (1) अनुच्छेद 60 (2) अनुच्छेद 164
(3) अनुच्छेद 270 (4) अनुच्छेद 350

उत्तर—(2) (वरिष्ठ अध्यापक (NON TSP GK)— 2019)

73. निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डीग-गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया?

- (1) जगन्नाथ पहाड़िया ; 13 जुलाई, 1981
(2) शिव चरण माथुर ; 23 फरवरी, 1985
(3) हरिदेव जोशी ; 20 जनवरी, 1988
(4) मोहन लाल सुखाड़िया ; 16 फरवरी, 1980

(VDO 27-12-2021)

व्याख्या—(2) 23 फरवरी, 1985 को चुनाव अभियान के दौरान डीग गोली काण्ड के कारण कांग्रेस उच्च सत्ता के निर्देश पर शिव चरण माथुर ने त्याग पत्र दे दिया।

74. निम्न में से कौनसा कथन गलत है? (VDO 28-12-2021)

- (1) मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जाती है।
(2) राज्य सरकारें विधायकों में से संसदीय सचिवों की नियुक्ति करती रही हैं।
(3) मुख्यमंत्री संसदीय सचिव की नियुक्ति करते हैं और पद की शपथ दिलाते हैं।
(4) तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप शामिल है।

व्याख्या—(4) संसदीय सचिव को पद की शपथ मुख्यमंत्री द्वारा दिलायी जाती है। राजस्थान में संसदीय सचिव की शुरुआत मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय की गई।

75. राजस्थान में मंत्रिपरिषद् की किसी बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में कौन करता है?

- (1) गृह मंत्री (2) वित्त मंत्री
(3) राजस्व मंत्री
(4) मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य मंत्री

उत्तर—(4) (Deputy Commandant- 2020)

76. राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन, मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं था/थी? (मूल्यांकन अधिकारी—2020)

- (1) टीकाराम पालीवाल (1952) (2) जगन्नाथ पहाड़िया (1980)
(3) वसुंधरा राजे (2003) (4) बरकतुल्लाह खान (1971)

उत्तर—(2)

77. निम्नांकित अधिकारियों में से कौन राजस्थान में मंत्रिपरिषद् के सचिव के रूप में कार्य करता है?

- (1) प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग (2) मुख्य सचिव
(3) प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
(4) अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग

उत्तर—(2) (मूल्यांकन अधिकारी—2020)

78. राजस्थान में निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी पदभार संभाला था?

- (1) प्रतिभा पाटिल (2) कृष्णकांत
(3) हरिदेव जोशी (4) भैरों सिंह शेखावत

(राज. पुलिस 6th ast Shift- 2020)

व्याख्या—(4) राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो भारत के 11वें उपराष्ट्रपति बने।

79. निम्नलिखित में से कौन से नेता 'बाबोसा' कहलाते हैं?

- (1) कृष्णकांत (2) हरिदेव जोशी
(3) जगन्नाथ पहाड़िया (4) भैरों सिंह शेखावत

उत्तर—(4) (राज.पुलिस 6th 2nd Shift- 2020)

3

राज्य विधानमंडल

1. संविधान के अनुच्छेद 191(1) के अन्तर्गत राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए—

- (i) ऐसे प्रश्नों पर राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा।
(ii) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।

- (1) केवल (ii) सही है (2) केवल (i) सही है
(3) (i) व (ii) दोनों सही हैं
(4) न तो (i) ना ही (ii) सही है

उत्तर—(3) (असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत विभाग) 2024)

2. राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? (असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत विभाग) 2024)

- (1) राजस्थान के राज्यपाल
(2) मुख्य न्यायमूर्ति, राजस्थान उच्च न्यायालय
(3) राजस्थान विधानसभा के निवर्तमान स्पीकर
(4) कोई नहीं

व्याख्या—(4) विधानसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता है, क्योंकि वह पूर्व में विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है।

3. राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? (Archives Department (Chemist) 2024)

- (1) अशोक गहलोत (2) टीकाराम जूली
(3) शांति धारीवाल (4) गोविन्द सिंह डोटासरा

उत्तर—(2)

4. राजस्थान में, अनुसूचित जाति के लिये लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या है— (BSTC-2024)

- (1) 4 और 34 (2) 3 और 25
(3) 4 और 25 (4) 3 और 34

व्याख्या—(1) राजस्थान से लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें 4 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं, जिसमें 34 अनुसूचित जाति और 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।

5. राजस्थान की 16वीं विधानसभा में महिला विधायकों का प्रतिशत है— (PTET-2024)

- (1) 10% (2) 12%
(3) 15% (4) 20%

व्याख्या—(1) 16वीं विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या 20 है। 20 महिला विधायकों में से 9 भाजपा, 9 कांग्रेस व 2 निर्दलीय विजय हुई।

6. राज्य विधान सभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है— (Raj. Police 2024 K-2)

- (1) 25 वर्ष (2) 26 वर्ष
(3) 21 वर्ष (4) 18 वर्ष

व्याख्या—(1) विधानसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु तथा विधानपरिषद् के सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु पूर्ण हो।

7. राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? (Raj. Police 2024 K-2)

- (1) 40 (2) 50
(3) 60 (4) 30

व्याख्या—(1) अनुच्छेद-171(1)— राज्य की विधानपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई (1/3) से अधिक नहीं होगी। लेकिन किसी राज्य की विधानपरिषद् के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी।

8. भारत के प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गये.....से अनाधिक सदस्यों से मिलकर बनती है।

- (1) 500 (2) 545
(3) 525 (4) 515

(Asst. Pro. (Pol.Sci.)-2024)

व्याख्या—(1) अनुच्छेद-170(1)— अनुच्छेद 333 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गये अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी।

9. राजस्थान में, 1977 में छठी विधानसभा के निर्वाचन में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने भाग लिया था?

- (1) 6 (2) 3
(3) 5 (4) 4

(Asst. Pro. (Pol.Sci.)-2024)

4

राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं नियम

1. राजस्थान विधानसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?

- (1) हमीर सिंह भायल (2) जेठानन्द व्यास
(3) कंवर लाल (4) गणेश घोगरा

(असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत विभाग) 2024)

व्याख्या—(1) याचिका समिति का गठन 1952 में किया गया। यह समिति विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत की जाती है, जिसमें अधिकतम 15 सदस्य होते हैं तथा इसका कार्यकाल एक वर्ष होता है।

2. राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाये जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है:

- (1) विधानसभा अध्यक्ष (2) नेता प्रतिपक्ष
(3) मुख्यमंत्री (4) मुख्य सचेतक

(वरिष्ठ अध्यापक ग्रुप—A (संस्कृत शिक्षा) 2023)

व्याख्या—(1) जब कोई विधेयक, जो सदन द्वारा पारित हो चुका हो, राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाया जाए तो, पुनर्विचार के लिए निर्देशित मुद्दा या सिफारिश किए गए संशोधन अध्यक्ष द्वारा सदन के सामने रखे जाएंगे और उन पर उसी प्रकार से वाद—विवाद किया जायेगा और मत लिए जाएंगे जैसे कि किसी विधेयक के संशोधन पर या किसी ऐसी अन्य रीति से, जिसे अध्यक्ष सदन द्वारा उन पर विचार किए जाने के लिए अत्यन्त सुविधाजनक समझे।

3. निम्नांकित में से कौन सी, राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता की शर्त नहीं है?

- (1) उसका सम्बन्ध केवल एक माँग से होगा।
(2) उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा।
(3) उसमें वर्तमान विधियों का संशोधन या निरसन करने के लिए सुझाव नहीं दिये जायेंगे।
(4) वह उस विषय का निर्देश नहीं करेगी जो मुख्यतया राज्य सरकार का विषय नहीं हो।

(वरिष्ठ अध्यापक ग्रुप—A - 2023)

व्याख्या—(2) उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

4. राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िये—

(वरिष्ठ अध्यापक ग्रुप—B - 2023)

- (i) अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो सदन तय करे।
(ii) उस तय तिथि की सूचना राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को भेजेंगे।
सही कथन पहचानिये—

(1) (i) व (ii) दोनों सही हैं।

(2) (i) व (ii) दोनों गलत हैं।

(3) (i) सही व (ii) गलत है। (4) (i) गलत व (ii) सही है

व्याख्या—(2) अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि राज्यपाल द्वारा निश्चित की जायेगी और उस तिथि की सूचना प्रत्येक सदस्य को सचिव द्वारा दी जायेगी।

5. राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

(1) कोई सदस्य जो सदन में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है, अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को सूचित करेगा।

(2) यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है और अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना अथवा ज्ञान नहीं है, अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है।

(3) यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त होता है, अध्यक्ष स्वयं की संतुष्टि के लिए कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है, जाँच करवा सकता है, जैसा वह उचित समझे।

(4) कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है।

(वरिष्ठ अध्यापक ग्रुप—C - 2023)

व्याख्या—(4) कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किये जाने से पूर्व अपना त्याग पत्र वापस ले सकेगा।

6. राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा—समिति के सदस्यों का कार्यकाल है

(वरिष्ठ अध्यापक ग्रुप—C - 2023)

- (1) एक वर्ष (2) दो वर्ष
(3) पाँच वर्ष (4) चार वर्ष

व्याख्या—(1) लोक लेखा—समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल 01 वर्ष का होता है। इस समिति के अध्यक्ष विपक्ष दल का सदस्य होता है।

7. राजस्थान विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा?

(वरिष्ठ अध्यापक ग्रुप—D - 2023)

- (1) राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष
(2) राजस्थान विधानसभा का नेता
(3) राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का नेता
(4) सदन का कोई सदस्य जिसे स्पीकर नियुक्त करें।

उत्तर—(1)

5

संसद में राजस्थान

1. लोकसभा आम चुनाव 2024 में, राजस्थान में स्वीप गतिविधियों के तहत, किस जिले के कितने लोगों ने मतदान की एक साथ शपथ लेकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन में रिकॉर्ड दर्ज करवाया?

(1) सीकर में 9.16 लाख (2) झुंझुनूं में 7.16 लाख
(3) सीकर में 7.16 लाख (4) झुंझुनूं में 9.16 लाख

उत्तर—(1) (Archives Department (Chemist) 2024)

2. राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं?

(1) 21 (2) 13
(3) 25 (4) इनमें से कोई नहीं

(REET L1 - 2015)(वरिष्ठ अध्यापक— 2013)(EO/RO-2023)

व्याख्या—(3) राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं जिनमें से 4 अनुसूचित जाति व 3 अनुसूचित जनजाति की सीटें आरक्षित हैं।

3. निम्नलिखित में से कौन, राजस्थान से राज्यसभा चुनाव 2022 में निर्वाचित नहीं हुआ था? (CET Graduation- 2023)

(1) श्री घनश्याम तिवारी (2) श्री प्रमोद कुमार
(3) श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक
(4) श्री सुभाष चन्द्रा

व्याख्या—(4) राज्यसभा चुनाव 2022 में 04 सांसद निर्वाचित हुए, जो निम्न हैं— घनश्याम तिवारी, रणदीपसिंह सुरजेवाला, प्रमोद कुमार, मुकुल बालकृष्ण वासनिक। राज्यसभा चुनाव 2024 में निर्वाचित सांसद— चुन्नीलाल गरासिया, मदन राठौड़, के.सी. वेणुगोपाल व सोनिया गाँधी।

के.सी. वेणुगोपाल ने अलाप्पुझा सीट (केरल) से 2024 में लोकसभा चुनाव जीता, इसके बाद इन्होंने राजस्थान राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यसभा उपचुनाव 2024 में रवनीत सिंह निर्वाचित हुए।

4. निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? (CET Graduation- 2023)

(1) गायत्री देवी (2) शारदा भार्गव
(3) प्रियंका चतुर्वेदी (4) सोनल मानसिंह

व्याख्या—(2) शारदा भार्गव राजस्थान से तीन बार लगातार (1952-1966) राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुईं।

5. राजस्थान से अधिकतम चार बार राज्य सभा के लिए कौन निर्वाचित हुआ? (वनरक्षक— 2022)

(1) अशोक गहलोत (2) गिरिजा व्यास
(3) ज्ञान प्रकाश पिलानिया (4) राम निवास मिर्धा

व्याख्या—(4) राजस्थान से सर्वाधिक बार राज्यसभा सदस्य चुने जाने वाले व्यक्ति— रामनिवास मिर्धा (4 बार), जसवंत सिंह (4 बार)।

6. लोक सभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं? (APRO- 2022)

(1) 12 (2) 16
(3) 20 (4) 25

उत्तर—(4)

7. निम्नांकित में से कौन, राजस्थान से राज्यसभा में सबसे ज्यादा अवधि के लिए प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद है? (H.M. प्रवेशिका—2021)

(1) ऊषी खान (2) शारदा भार्गव
(3) लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (4) शांति पहाड़िया

उत्तर—(2)

8. लोकसभा में राजस्थान से कितने सांसद चुने जाते हैं?

(1) 25 (2) 28
(3) 33 (4) 41

(राज. पुलिस 7th 1st Shift- 2020)

नोट—(3) पुलिस विभाग ने इस प्रश्न का उत्तर 33 माना है, जो कि गलत है, क्योंकि राजस्थान से 25 लोकसभा सांसद चुने जाते हैं।

9. दिसंबर 2019 तक के अनुसार, भारतीय संसद के उच्च सदन (राज्यसभा) में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कितने सदस्यों द्वारा किया जा रहा है?

(1) 40 (2) 20
(3) 10 (4) 5

(राज. पुलिस 7th 1st Shift- 2020)

व्याख्या—(3) 1952 के राज्यसभा चुनाव में राजस्थान की 9 सीटें थी, जो कि 1960 में बढ़ाकर 10 कर दी गई, जो वर्तमान तक है।

10. दिसंबर 2019 तक, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं?

(1) कोटा-बूंदी (2) जयपुर
(3) अजमेर (4) बीकानेर

उत्तर—(1)

(राज.पुलिस 8th 1st Shift- 2020)

6

उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय

1. राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई?
 (1) 1951 (2) 1948
 (3) 1949 (4) 1950

(CET Graduation (Shift-4)-2024)

व्याख्या—(3) राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त, 1949 में की गई।

2. किस भारतीय संविधान संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी? (CET Graduation (Shift-2)-2024)
 (1) 18वाँ संविधान संशोधन (2) 15वाँ संविधान संशोधन
 (3) 16वाँ संविधान संशोधन (4) 17वाँ संविधान संशोधन

व्याख्या—(2) 15वें संविधान संशोधन 1963 की धारा 4(क) द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों के पद धारण करने की आयु 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष कर दी गई है।

3. राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट (प्रिन्सिपल सीट) कहाँ स्थित है? (CET Graduation (Shift-1)-2024)
 (1) कोटा (2) जोधपुर
 (3) बाड़मेर (4) अजमेर

उत्तर—(2)

4. राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में कितनी जजशिप हैं?
 (1) 17 (2) 19
 (3) 21 (4) 14

(असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत विभाग) 2024)

व्याख्या—(2) उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ (जोधपुर) के क्षेत्राधिकार में 19 न्यायालय आते हैं— जोधपुर जिला, जोधपुर मेट्रोपोलिटन, बालोतरा, जैसलमेर, जालौर, सिरौही, पाली, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, मेड़ता, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा।

5. निम्नलिखित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था, जब भारत के राष्ट्रपति ने 1956 में भारत के मुख्य न्यायाधीश एस. आर. दास की सिफारिश पर राजस्थान के जजों की नियुक्ति के नये वारंट जारी किये थे? (असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत विभाग) 2024)
 (1) इन्द्र नाथ मोदी (2) कैलाश वांचू
 (3) डी. एस. दवे (4) के. के. शर्मा

व्याख्या—(2) वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद 01 नवम्बर, 1956 को राजस्थान को 'ए' श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस.आर. दास की अनुशंसा पर भारत के राष्ट्रपति ने राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के नये अधिपत्र (वारंट) जारी किए, जिस पर 01 नवम्बर, 1956 को नए सिरे से शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उस समय राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कैलाशनाथ वांचू थे।

6. संविधान के अनुसार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है?
 (1) राज्य के राज्यपाल के पास (2) राज्य के मुख्यमंत्री के पास
 (3) भारत के राष्ट्रपति के पास
 (4) भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास

(Raj. Police 2024 K-2)

व्याख्या—(4) अनुच्छेद 217(1)— उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जायेगी और किसी अन्य दशा में तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है।

7. उच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत रिट (याचिका) जारी कर सकते हैं? (Raj. Police 2024 L-1)
 (1) 220 (2) 221 (3) 213 (4) 226

व्याख्या—(4) अनुच्छेद 226 में मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है— बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा।

8. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? (Raj. Police 2024 L-2)
 (1) प्रधानमंत्री (2) मुख्यमंत्री (3) राज्यपाल (4) राष्ट्रपति

व्याख्या—(4) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् की जाती है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श करने के बाद की जाती है।

7

राज्य सचिवालय व मुख्य सचिव

1. राजस्थान के मुख्य सचिवों को उनकी नियुक्ति के अनुसार पुराने से नये के क्रम में लगाएँ।

- (a) श्री राजीव स्वरूप
(b) श्रीमती उषा शर्मा
(c) श्री ओम प्रकाश मीणा
(d) श्रीमती कुशल सिंह

नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें:

- (1) (a), (d), (b), (c) (2) (b), (d), (a), (c)
(3) (b), (c), (d), (a) (4) (c), (d), (a), (b)

(CET 10 + 2 (Shift-6)-2024)

नोट—(*) श्रीमती कुशल सिंह (27-02-2009 से 31-10-2009), श्री ओमप्रकाश मीणा (30-06-2016 से 30-06-2017), श्री राजीव स्वरूप (03-07-2020 से 31-10-2020) व श्रीमती उषा शर्मा (01-02-2022 से 31-12-2023)।

2. राजस्थान के मुख्य सचिव (05 सितम्बर 2024 को) कौन थे? (CET 10 + 2 (Shift-2)-2024)

- (1) सतीश कुमार (2) जगदीश मीणा
(3) सुभाष चन्द (4) सुधांश पंत

व्याख्या—(4) श्री सुधांश पंत ने राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में 01 जनवरी, 2024 को पदभार संभाला।

3. निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? (RAS Pre.- 2015)(CET 10 + 2 (Shift-2)-2024)

- (1) श्री वी. नारायण (2) श्री अपूर्व चन्द्रा
(3) श्री के. राधाकृष्णन (4) श्री राजेश भूषण

(वरिष्ठ अध्यापक ग्रुप—B 2017)

व्याख्या—(3) 13 अप्रैल 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव के. राधाकृष्णन बने। ये केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रथम मुख्य सचिव थे।

4. राजस्थान प्रशासन प्रणाली (सिस्टम) के उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय है: (CET 10 + 2 (Shift-2)-2024)

निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें—

- (1) मंत्री (2) सरकारी सचिवालय
(3) राज्यपाल कार्यालय (4) मुख्यमंत्री कार्यालय

उत्तर—(2)

5. राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यालय में डी.सी. सामन्त की नियुक्ति के साथ एक अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद कब सृजित किया गया?

- (1) 2004 (2) 2008 (3) 2001 (4) 2006

उत्तर—(*) (असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत विभाग) 2024)

6. 1963 में, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति द्वारा सचिवालय के संबंध में दिये सुझावों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें और नीचे दिये गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए—

(i) सचिव के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष से अधिक के लिये नहीं होनी चाहिए।

(ii) सचिव के पद पर केवल योग्यता नियुक्ति का आधार होनी चाहिए, न कि वरिष्ठता।

कूट— (असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत विभाग) 2024)

- (1) केवल (ii) सही है (2) (i) और (ii) दोनों सही है
(3) केवल (i) सही हैं (4) (i) और (ii) दोनों गलत है

व्याख्या—(1) इस समिति के सुझाव के अनुसार सचिवालय में सचिव या उपसचिव का कार्यकाल सामान्यतः 4 वर्ष का होना चाहिए और किसी भी स्थिति में 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। कोई भी अधिकारी लगातार 5 वर्ष से अधिक समय तक सचिवालय में नहीं रहना चाहिए। सरकार में सचिवों के पद केवल वरिष्ठता के आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता के आधार पर भरे जाने चाहिए।

7. निम्नांकित में से कौन सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (एस. एस. ए. ए. टी.) के शासी निकाय के अध्यक्ष हैं?

(1) निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (एस. एस. ए. ए. टी.)

(2) मुख्यमंत्री

(3) वित्त मंत्री

(4) मुख्य सचिव

उत्तर—(4) (असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत विभाग) 2024)

8. सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव हैं:

(1) राजीव स्वरूप (2) एन.सी. गोयल

(3) निरंजन कुमार आर्य (4) सी.के. मैथ्यू

(वरिष्ठ अध्यापक ग्रुप—ए—2023)

व्याख्या—(डिलीट) राजस्थान में सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव एच.एम. माथुर हैं। प्रश्न के विकल्प सही नहीं होने के कारण यह प्रश्न डिलीट किया गया है।

8

संभाग व जिला प्रशासन व्यवस्था

1. जिला स्तर पर, राज्य सरकार के काम के लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन है? (Raj. Police 2024 K-2)

- (1) क्षेत्रीय आयुक्त (2) जिला अधिकारी
(3) उप-खंड अधिकारी (4) पुलिस अधीक्षक

व्याख्या—(2) जिला कलेक्टर जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है। वह जिले का मुख्य कार्यकारी, प्रशासनिक एवं राजस्व अधिकारी होता है।

2. उपखण्ड का प्रशासन किसके नियंत्रण में है?

- (1) विकास अधिकारी
(2) एसडीएम (सब डिविजनल मजिस्ट्रेट)
(3) जिला प्रमुख (4) सत्र न्यायाधीश

(Raj. Police 2024 K-2)

व्याख्या—(2) जिले को उपखण्डों में विभाजित किया गया है। उपखण्ड का सर्वोच्च अधिकारी S.D.O./S.D.M. होता है। सामान्यतः यह राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है।

3. संसद, विधान सभा और स्थानीय निकायों के लिए जिले स्तर पर चुनाव कौन नियंत्रित और प्रबंधित करता है?

- (1) क्षेत्रीय आयुक्त (2) प्रभारी मंत्री
(3) निर्वाचन आयोग (4) जिला मजिस्ट्रेट

(Raj. Police 2024 L-2)

व्याख्या—(4) जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिले में होने वाले सभी प्रकार के चुनावों को सम्पन्न करवाना तथा उन पर नियंत्रण व निरीक्षण करना।

4. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? (VDO 27-12-2021)(Raj. Police 2024 L-1)

- (1) पुलिस अधीक्षक (2) आयुक्त नगर निगम
(3) जिला कलेक्टर (4) सीईओ (जिला परिषद)

व्याख्या—(3) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण— राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) के तहत प्रत्येक जिले में एक 'जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' की स्थापना की गई है, जिसका अध्यक्ष 'जिला कलेक्टर' होता है।

5. भारत में जिला प्रशासन में कलेक्टर का पद किस वर्ष में बनाया गया था? (Raj. Police 2024 L-2)

- (1) 1852 (2) 1764
(3) 1872 (4) 1772

व्याख्या—(4) गर्वनर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में भारत में पहली बार 1772 ई. में कलेक्टर का पद सृजित हुआ। जिसे 1773 में समाप्त कर दिया गया तथा 1781 में पुनः सृजित किया गया।

6. तहसीलदार की नियुक्ति होती है। (RAS Pre-2023)

- (1) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा
(2) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा
(3) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा
(4) राजस्व मंडल द्वारा

व्याख्या—(4) उपखण्ड को तहसील में विभाजित किया गया है। तहसीलदार, राजस्थान तहसील सेवा का अधिकारी होता है। तहसीलदार की नियुक्ति राजस्व मण्डल द्वारा की जाती है।

7. राजस्थान में राजस्व मण्डल की स्थापना कब हुई?

- (1) 1947 (2) 1949
(3) 1951 (4) 1955

(JEN Elec. Mech. Diploma- 2022)(CET Graduation- 2023)

व्याख्या—(2) राजस्थान राजस्व मण्डल की स्थापना 01 नवम्बर, 1949 में की गई। इसका मुख्यालय अजमेर में स्थित है।

8. किस अधिनियम द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया?

- (1) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2004
(2) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
(3) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2007
(4) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2008

उत्तर—(2) (संरक्षण अधिकारी— 2023)

9. राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? (JEN Elec. Mech. Diploma- 2022)

- (1) 1977 (2) 1985 (3) 1987 (4) 1989

व्याख्या—(3) 24 अप्रैल, 1962 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। 26 जनवरी, 1987 को मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के समय 6 संभागों के साथ संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत हुई।

10. जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है?

- (1) भारतीय राजस्व सेवा (2) राज्य सिविल सेवा
(3) भारतीय प्रशासनिक सेवा (4) भारतीय पुलिस सेवा

(वनरक्षक— 2022)

9

पंचायती राज

1. इन संगठनों में कौन सा संगठन राजस्थान पंचायती राज प्रणाली के क्रम में सबसे ऊँचे स्तर पर है?
- (1) पंचायत समिति (2) ग्राम पंचायत
(3) केन्द्रीय पंचायत (4) जिला परिषद्
(CET 10 + 2 (Shift-6)-2024)

व्याख्या—(4) जिला स्तर पर जिला परिषद्, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति व ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है।

2. _____ पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था? (अनुसंधान सहायक-2017) (CET 10 + 2 (Shift-5)-2024)
- (1) उत्तर प्रदेश (2) पंजाब
(3) गुजरात (4) राजस्थान
उत्तर—(4)
3. भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस निर्देशक सिद्धान्त के अनुसार राज्य को ग्राम पंचायत का संगठन करने और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करना है?
- (1) अनुच्छेद-40 (2) अनुच्छेद-42
(3) अनुच्छेद-38 (4) अनुच्छेद-39
(CET 10 + 2 (Shift-5)-2024)

व्याख्या—(1) अनुच्छेद 38— राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।

अनुच्छेद 39— राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति-तत्त्व।

अनुच्छेद 42— काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबन्ध।

4. नीचे दो कथन दिए गए हैं: (CET 10 + 2 (Shift-4)-2024)
- कथन-(I) : पंचायती राज व्यवस्था की उच्चतम इकाई जिला परिषद् या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। जिला परिषद् ग्रामीण के प्रगति की योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित अधीक्षण शक्ति है।
- कथन-(II) : जिला परिषद् (डिस्ट्रिक्ट काउंसिल) की व्यवस्था उस क्षेत्र के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों अर्थात् जिला परिषद् के MLA, MP द्वारा की जाती है।
- उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें:
- (1) कथन (I) और कथन (II) दोनों गलत हैं।
(2) कथन (I) सही है किन्तु कथन (II) गलत है।
(3) कथन (I) गलत है किन्तु कथन (II) सही है।
(4) कथन (I) और कथन (II) दोनों सही हैं।

व्याख्या—(2) धारा-14 के अनुसार जिला परिषद् का गठन प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य व सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष से मिलकर होगा, लेकिन जिला परिषद् के सदस्यों की संख्या 17 से कम नहीं होगी।

5. बलवंत राय मेहता समिति निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से स्थापित की गयी थी? (CET 10 + 2 (Shift-4)-2024) (निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें):
- (1) लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के सुझाव देने के लिए
(2) उस समय ग्राम पंचायत की कार्य शैली की रिपोर्ट देने के लिए
(3) सामुदायिक विकास परियोजनाओं को बेहतर दक्षता से लागू करने के सुझाव देने के लिए
(4) ग्राम पंचायत के पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का निवेश करने के लिए
उत्तर—(3)
6. पंचायती राज एक की व्यवस्था है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें:
- (1) स्थानीय सरकार (2) स्थानीय प्रशासन
(3) स्थानीय स्वशासन (4) ग्रामीण स्थानीय स्वशासन
उत्तर—(4) (CET 10 + 2 (Shift-3)-2024)
7. पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम कोरम क्या है?
- (1) एक चौथाई (2) छठवां भाग
(3) आठवां भाग (4) दसवां भाग
(CET 10 + 2 (Shift-3)-2024)

व्याख्या—(4) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 धारा-8(ख) के अनुसार ग्राम सभा की बैठकों की गणपूर्ति के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 1/10 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।

8. पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के बारे में असत्य कथन का चयन करें:
- (1) त्रिस्तरीय पंचायती राज के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था लाना।
(2) यदि पंचायती संस्थाओं का अधिक्रमण किया जाता है, तो एक वर्ष के भीतर चुनाव कराया जाना चाहिए।
(3) एस सी और एस टी के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर
(4) पंचायती राज मामलों में राजनीतिक दलों की प्रत्येक स्तर पर भागीदारी

(CET 10 + 2 (Shift-2)-2024)

71. राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी? (APRO- 2022)

- (1) 1950 (2) 1947 (3) 1956 (4) 1953

उत्तर—(4)

72. ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के सदस्य कौन-कौन होते हैं?

- (1) केवल वॉर्ड पंच (2) केवल गाँव के पुरुष सदस्य
(3) गाँव के सभी निवासी
(4) केवल मतदाता सूची में पंजीकृत ग्रामवासी

उत्तर—(4) (Asst. Agri Officer- 2022)

73. भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? (PTI Grade III - 2022)

- (1) प्रस्तावना
(2) मौलिक अधिकार
(3) राज्य नीति के निदेशक तत्व
(4) दसवीं अनुसूची

व्याख्या—(3) भारतीय संविधान के भाग-4 (राज्य के नीति-निदेशक तत्व) के अनुच्छेद-40 में ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित प्रावधान है।

74. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? (PTI Grade III - 2022)

- (1) 23 अप्रैल, 1994 (2) 23 अप्रैल, 1995
(3) 24 अप्रैल, 1994 (4) 24 अप्रैल, 1995

व्याख्या—(1) वर्ष 1994 में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम-1953 को संशोधित कर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम-1994 बनाया गया। राजस्थान के राज्यपाल द्वारा 23 अप्रैल, 1994 को राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम-1994 को स्वीकृति प्रदान की गई।

75. राज्य निर्वाचन आयोग (एस.ई.सी.), राजस्थान पंचायती राज संस्थानों (पी.आर.आई.) के चुनाव आयोजित करता है। इन चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (राजस्थान पुलिस- 2022)

- (1) पहला चुनाव : 1965 (2) दूसरा चुनाव : 1970
(3) तीसरा चुनाव : 1978 (4) चौथा : 1988

व्याख्या—(3) राज्य में अब तक पंचायती राज के चुनाव निम्न संस्थाओं द्वारा करवाए गए हैं—

1. पंचायती राज विभाग द्वारा— वर्ष 1960, 1965, 1978, 1981 व 1995
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा— वर्ष 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 व 2020

76. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की किस धारा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख है? (स्कूल व्याख्याता जीके एवं जीएस- 2022)

- (1) 81 (2) 82
(3) 83 (4) 84

व्याख्या—(4) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-84 में मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य अधिकारियों की शक्तियों और कार्यों का प्रावधान किया गया है।

77. राजस्थान में ई-पंचायत के उद्देश्य हैं—

- I. पंचायती राज विभाग की उत्पादकता में वृद्धि
II. ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की आन्तरिक प्रक्रिया का सुव्यवस्थीकरण
III. ग्रामीण समस्याओं का मात्र तीव्र एकत्रीकरण सही विकल्प हैं—

- (1) I, II, III (2) I, III (3) I, II (4) II, III
(स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान- 2022)

व्याख्या—(3) राज ई-पंचायत— यह मिशन बोर्ड परियोजना के अन्तर्गत तैयार किया गया सॉफ्टवेयर है, जिसका उद्देश्य पंचायतीराज संस्थाओं को सशक्त एवं पारदर्शी करने के साथ-साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की आंतरिक प्रक्रिया को भी सशक्त और सुव्यवस्थित करना है।

78. राजस्थान में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होते समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे?

- (1) हरिदेव जोशी (2) शिवचरण माथुर
(3) भैरोंसिंह शेखावत (4) राष्ट्रपति शासन

(स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान- 2022)

व्याख्या—(4) राजस्थान में 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम-1992 लागू होने के समय राज्य में चौथा राष्ट्रपति शासन काल लागू था।

79. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा ग्राम सभाओं के गठन का प्रावधान निम्नांकित किया गया है?

- (1) अनुच्छेद 243(b) (2) अनुच्छेद 243(D)
(3) अनुच्छेद 243(E) (4) अनुच्छेद 243(M)

(स्कूल व्याख्याता लोक प्रशासन- 2022)

नोट—(1) भारतीय संविधान के अनुच्छेद-243क(A) में ग्राम सभाओं के गठन का प्रावधान किया गया है।

80. 24 अप्रैल को "पंचायती राज दिवस" प्रथम बार निम्नांकित में से किस वर्ष मनाया गया था?

- (1) 1995 (2) 2000 (3) 2005 (4) 2010

(स्कूल व्याख्याता लोक प्रशासन- 2022)

10

नगरीय स्वशासन

1. किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया?
 (1) 44वां संवैधानिक संशोधन (2) 74वां संवैधानिक संशोधन
 (3) 73वां संवैधानिक संशोधन (4) 42वां संवैधानिक संशोधन
 उत्तर—(2) (CET 10 + 2 (Shift-3)-2024)
2. शहरी स्थानीय निकाय में महिलाओं, हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया?
 (1) 74वें (2) 65वें (3) 68वें (4) 73वें

(CET Graduation (Shift-4)-2024)

व्याख्या—(1) अनुच्छेद-243न(3)— प्रत्येक नगर पालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई (1/3) स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

3. भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 W के अनुसार नगरपालिकाओं का कौनसा विषय नहीं है?
 (असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत विभाग) 2024)
- (1) बाजार और मेले (2) सड़कें और पुल
 (3) अग्निशमन सेवाएँ (4) जन्म-मरण सांख्यिकी

व्याख्या—(1) 12वीं अनुसूची में वर्णित 18 विषय शामिल किए गए हैं, जो कि निम्न है— नगरीय योजना, जिसमें शहरी योजना भी है। भू-उपयोग नियमन व भवन निर्माण। आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनाएँ। सड़कें एवं पुल। घरेलू, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए जल प्रबन्धन। सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई एवं कचरा प्रबन्धन। अग्निशमन सेवाएँ। जन्म मृत्यु पंजीयन।

4. भारतीय संविधान की कौन-सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है?
 (1) आठवीं (2) दसवीं
 (3) बारहवीं (4) ग्यारहवीं

(CET 10+2 2023)(Hostel Superintendent -2024)

व्याख्या—(3) 74वें संविधान संशोधन-1992 के द्वारा संविधान में एक नया भाग-9(क) जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद-243 (P) से 243 (ZG) तक (कुल 18 अनुच्छेद) तथा अनुसूची-12 (18 विषय) जोड़ी गई, जो नगर पालिकाओं से संबंधित है।

5. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 5 के अनुसार, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नगरपालिका परिषद् की स्थापना की जानी चाहिए? (EO/RO-2023)

- (1) छोटे शहरी क्षेत्र (2) बड़े शहरी क्षेत्र
 (3) संक्रमणकालीन क्षेत्र (4) प्रत्येक क्षेत्र

व्याख्या—(1) नगर पालिका की स्थापना और निगमन (धारा-5)—
 1. प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र में एक नगर पालिका बोर्ड की स्थापना की जायेगी।

2. प्रत्येक लघुत्तर नगरीय क्षेत्र (छोटे शहरी क्षेत्र) में एक नगर परिषद् की स्थापना की जायेगी।

3. प्रत्येक वृहत्तर नगरीय क्षेत्र (बड़े शहरी क्षेत्र) में एक नगर निगम की स्थापना की जायेगी।

6. निम्नलिखित में से कौन चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक नगरपालिका में विभाजित किए जाने वाले वार्डों की संख्या निर्धारित करता है?
 (EO/RO-2023)
- (1) केंद्र सरकार (2) राज्य सरकार
 (3) राज्य के राज्यपाल (4) भारत के राष्ट्रपति

व्याख्या—(2) किसी नगर पालिका के सभी स्थान वार्डों के नाम से जाने जाने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गये व्यक्तियों से भरे जाएंगे। ऐसे वार्डों की संख्या 13 से कम नहीं होगी, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा समय-समय पर नियत करेगी।

7. निम्नलिखित में से कौन किसी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है जो उस समिति का सदस्य होता है?
 (1) मुख्यमंत्री
 (2) नेता प्रतिपक्ष
 (3) मुख्य नगरपालिका अधिकारी
 (4) नगरपालिका के अध्यक्ष

(EO/RO-2023)

व्याख्या—(4) राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा-57 के अनुसार नगरपालिका का अध्यक्ष यदि किसी समिति का सदस्य है, तो वह उस समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।

8. राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग, स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय कहाँ स्थित है? (EO/RO-2023)
- (1) जोधपुर (2) कोटा
 (3) जयपुर (4) उदयपुर

व्याख्या—(3) राजस्थान में स्थानीय निकाय विभाग की स्थापना 1950 की गई। इसके निदेशालय का मुख्यालय जयपुर में है।

11

प्रमुख आयोग

A

राजस्थान लोक सेवा आयोग

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है?

- (1) राज्यपाल
(2) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
(3) मुख्यमंत्री (4) राष्ट्रपति

(REET L- 2 (Sanskrit) 2023)(CET 10 + 2 (Shift-6)-2024)

व्याख्या—(1) अनुच्छेद— 316 (1)— राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

2. भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों के विषय में जानकारी देता है? (CET 10 + 2 (Shift-5)-2024)

- (1) अनुच्छेद 320 (2) अनुच्छेद 317
(3) अनुच्छेद 312 (4) अनुच्छेद 316

उत्तर—(1)

3. राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है?

- (1) अजमेर (2) जयपुर (3) जोधपुर (4) अलवर

(CET 10 + 2 (Shift-3)-2024)

व्याख्या—(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना के समय मुख्यालय जयपुर रखा गया था, लेकिन बाद में पी. सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर 21 अगस्त, 1958 को आयोग का मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया।

4. भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत, राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष आयोग द्वारा किए गये कार्य के बारे में किसे प्रतिवेदन प्रस्तुत करें?

- (1) मुख्यमंत्री (2) राज्यपाल
(3) विधानसभा (4) राष्ट्रपति

(CET 10 + 2 (Shift-2)-2024)

व्याख्या—(2) अनुच्छेद 323(2)— राज्य लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के राज्यपाल को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपेगा। राज्यपाल उस प्रतिवेदन को राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखवाता है।

5. राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस के द्वारा की जाती है?

- (1) राज्यपाल
(2) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
(3) अध्यक्ष यू पी एस सी (4) मुख्यमंत्री

उत्तर—(1) (CET 10 + 2 (Shift-1)-2024)

6. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को राजस्थान लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है?

- (1) अनुच्छेद 245 (2) अनुच्छेद 300 (A)
(3) अनुच्छेद 145 (g) (4) अनुच्छेद 320 (3)

(असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत विभाग) 2024)

व्याख्या—(4) अनुच्छेद—320(3)— निम्न मामलों में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।

(क)— सिविल सेवाओं में और सिविल पदों की भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर

(ख)— सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और अन्तरण करने में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धान्तों पर

(ग)— ऐसे व्यक्ति पर, जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सिविल सेवा कर रहा है, प्रभाव डालने वाले अनुशासन विषयों से जो अभ्यावेदन या याचिकाएँ हैं।

(ङ)— पेंशन के सम्बन्ध में तथा क्षतिपूर्ति मामलों में परामर्श किया जायेगा

7. राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं में चयन हेतु संवीक्षा परीक्षा का प्रारम्भ राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किस वर्ष से किया गया था?

- (1) 1982 (2) 1984
(3) 1988 (4) 1986

उत्तर—(*) (असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत विभाग) 2024)

8. राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन सस्पेंड कर सकता है? (Raj. Police 2024 K-2)

- (1) राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा
(2) राजस्थान के मुख्य सचिव द्वारा
(3) गवर्नर द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित एक समिति द्वारा
(4) राज्यपाल की सलाह पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा

B**राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग**

1. राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए सबसे उपयुक्त कथन की पहचान करें। वह रहा/रही हो:

- (1) समाज सेवक (2) विधान सभा के अध्यक्ष
(3) जिला न्यायाधीश
(4) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश

उत्तर—(4) (CET 10 + 2 (Shift-6)-2024)

2. राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? (CET 10+2 2023)(CET 10 + 2 (Shift-2)-2024)

- (1) कमला बेनीवाल (2) कांता भटनागर
(3) प्रतिभा पाटिल (4) शांता कुमारी

व्याख्या—(2) आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल श्रीमती कांता कुमारी भटनागर का है, इन्होंने 23 मार्च, 2000 से 11 अगस्त, 2000 तक अध्यक्ष पद संभाला।

3. राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन-सा कार्य नहीं है? (निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें):

- (1) मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों को हतोत्साहित करना।
(2) जेलों का दौरा करना और कैदियों की जीवन स्थिति का अध्ययन करना।
(3) लोगों के बीच मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करना।
(4) मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना और बढ़ावा देना।

(CET 10 + 2 (Shift-1)-2024)

व्याख्या—(1) मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना।

4. वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हैं? (CET Graduation (Shift-4)-2024)

- (1) न्यायमूर्ति गंगा राम मूलचंदानी (2) न्यायमूर्ति एन.के. जैन
(3) न्यायमूर्ति श्री रामचंद्र सिंह झाला
(4) न्यायमूर्ति प्रकाश तातिया

व्याख्या—(1) 26 जून, 2024 को श्री गंगाराम मूलचंदानी आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए, जो वर्तमान अध्यक्ष हैं।

5. राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?

- (1) 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो
(2) 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो
(3) 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो
(4) 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो

(CET Graduation (Shift-1)-2024)

व्याख्या—(4) आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष इनमें जो भी पहले हो। वर्ष 2019 में हुए संशोधन से पूर्व इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो, था।

6. मानव अधिकारों की पहली घोषणा कब की गई थी?

- (1) 1948 (2) 1947
(3) 1942 (4) 1946

(Raj. Police 2024 K-2)

व्याख्या—(1) अंतराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 10 दिसम्बर, 1948 को किया गया।

7. राज्य मानव अधिकार आयोग कितने समय के भीतर मामले सुन सकता है? (Raj. Police 2024 L-2)

- (1) 2 साल (2) 1.5 साल
(3) 1 साल (4) 6 महीने

व्याख्या—(3) आयोग द्वारा 1 वर्ष से पुराने मामलों की जाँच नहीं की जाती।

8. राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 1993 के मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के कौन-से अनुच्छेद के तहत की जाती है?

- (1) 21 (2) 22
(3) 24 (4) 27

(Raj. Police 2024 L-2)

व्याख्या—(2) धारा-22(1)—आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है।

9. निम्नलिखित में से कौन राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे? (Raj. Police 2024 L-2)

- (1) जस्टिस प्रेमचंद जैन (2) जस्टिस एन.के. जैन
(3) जस्टिस एस.एस. अहलूवालिया
(4) जस्टिस कांता भटनागर

व्याख्या—(1) जस्टिस प्रेमचंद जैन और जस्टिस एस.एस. अहलूवालिया दोनों ही राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। इसलिए यह प्रश्न डिलीट किये जाने योग्य है।

10. राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक उपरांत लागू हुए? (Assi. Pro.-2024)

- (1) 19 जनवरी, 2001 से (2) 19 अगस्त, 2001 से
(3) 19 जून, 2001 से (4) 19 मार्च, 2000 से

C

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग

1. अगस्त 2024 में राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? (CET 10+2 (Shift-5)-2024)

- (1) मधुकर गुप्ता (2) प्रेम सिंह मेहरा
(3) इन्द्रजीत खन्ना (4) ए. के. पांडे

व्याख्या—(1) 14 अगस्त, 2022 को श्री मधुकर गुप्ता राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए, जो वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त हैं।

2. वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे?

- (1) मधुकर गुप्ता (2) अमर सिंह राठौर
(3) एन.आर. भसीन (4) इन्द्रजीत खन्ना

उत्तर—(1) (CET Graduation (Shift-1)-2024)

3. राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौनसा कथन असत्य है? (असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत विभाग) 2024)

- (1) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए ग्यारहवें आम चुनाव सितम्बर-अक्टूबर 2020 में 25 जिलों के लिए संपादित किये गये।
(2) राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में किया गया।
(3) राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए उत्तरदायी है।
(4) राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है, जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है।

व्याख्या—(1) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए ग्यारहवें आम चुनाव सितम्बर-अक्टूबर 2020 में 21 जिलों में करवाये गये। शेष जिलों के आम चुनाव दिसम्बर 2021 तक पूर्ण करवाये गये।

4. राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। (RAS Pre-2023)

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया।
2. राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में यह एक सदस्यीय आयोग है।
(1) न तो 1 न ही 2 सही है (2) 1 व 2 दोनों सही है
(3) केवल 2 सही है (4) केवल 1 सही है

उत्तर—(2)

5. भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 K के तहत, राज्य चुनाव आयोग (SEC), राजस्थान का गठन किस वर्ष किया गया था? (EO/RO-2023)

- (1) 1947 (2) 1960 (3) 1994 (4) 1935

व्याख्या—(3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा-120 के तहत राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना के आदेश राज्यपाल द्वारा 17 जून, 1994 को जारी किए गए तथा आयोग ने अपना कार्य प्रारम्भ 1 जुलाई, 1994 से किया।

6. श्री मधुकर गुप्ता का पद है— (REET L-2 (Math) 2023)

- (1) राज्य सूचना आयुक्त, राजस्थान
(2) राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान
(3) मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार
(4) राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, राजस्थान

व्याख्या—(2) राजस्थान निर्वाचन आयुक्त के रूप में मधुकर गुप्ता ने 14 अगस्त, 2022 को पदभार संभाला।

7. किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की नियोग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? (वरिष्ठ अध्यापक ग्रुप-C - 2023)

- (1) विधानसभा अध्यक्ष (2) मुख्यमंत्री
(3) निर्वाचन आयोग (4) राष्ट्रपति

उत्तर—(3)

8. निम्नलिखित में से कौन, नवम्बर, 2021 तक राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहे हैं?

- (1) श्री टीका राम मीणा (2) श्री प्रवीण गुप्ता
(3) श्री बलदेव सिंह (4) श्री सुशील कुमार लोहानी
(राजस्थान पुलिस- 2022)

व्याख्या—(2) वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन (IAS) हैं।

9. राज्य निर्वाचन आयोग (एस.ई.सी.), राजस्थान का गठन में किया गया था। (राजस्थान पुलिस- 2022)

- (1) 1994 (2) 1990 (3) 1991 (4) 1989

उत्तर—(1)

(उद्योग निरीक्षक- 2018)

10. राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (Asst. Professor Exam- 2021)

- (A) राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 ट के अधीन अप्रैल, 1994 में हुआ।
(B) राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय आयोग है, जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है।
(C) राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव है, जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है।

- (1) केवल A (2) A व B (3) B व C (4) A, B व C

E

राजस्थान राज्य महिला आयोग

1. निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही हैं? (Assi. Pro.-2024)

(1) नगेंद्र बाला (2) सुमन शर्मा
(3) लाड कुमारी जैन (4) पवन सुराणा

व्याख्या—(1) राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख नगेंद्र बाला (कोटा) थी

2. राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित हैं?

(1) धारा 11 में (2) धारा 12 में
(3) धारा 13 में (4) धारा 10 में

(Assi. Pro.-2024)

व्याख्या—(1) धारा-11- आयोग के कार्य- महिलाओं के साथ किसी भी अनुचित व्यवहार की जाँच करना, उस पर विनिश्चय करना और उस मामले में की जाने वाली कार्यवाहियों की सरकार को सिफारिश करना। राज्यभर में पीड़ित महिलाओं की शिकायत का निवारण करना। महिलाओं के हितों की रक्षा करना एवं उन्हें न्याय दिलाना। लोक उपक्रमों में महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना।

3. राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौनसा/कौनसे कथन सत्य है/हैं? (VDO 27-12-2021)

(i) आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
(ii) आयोग का गठन 15 मई, 1999 को हुआ।
(iii) यह गैर-संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है।
(iv) इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना तथा उनकी जाँच करना है।

(1) (i), (ii) (2) (i), (ii), (iii)
(3) (ii), (iii), (iv) (4) (i), (ii), (iii), (iv)

व्याख्या—(3) राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

4. राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा? (VDO 27-12-2021)

(1) कांता कथूरिया (2) तारा भण्डारी
(3) लाड कुमारी जैन (4) गिरिजा व्यास

उत्तर—(4)

5. किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई? (VDO 28-12-2021)

(1) 1996 (2) 1997 (3) 1998 (4) 1999

व्याख्या—(4) राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 23 अप्रैल, 1999 को एक विधेयक राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक के पारित होने के बाद 15 मई, 1999 को राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी कर राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम-1999 की धारा-3 के तहत राजस्थान राज्य महिला आयोग (Rajasthan State Commission for Women) का गठन किया गया।

6. राजस्थान राज्य महिला आयोग है-

(1) सांविधिक निकाय (2) संवैधानिक निकाय
(3) नियामकीय निकाय
(4) अध्यादेश द्वारा बनाया गया है

(उद्योग विस्तार अधिकारी-2018)

व्याख्या—(1) राजस्थान राज्य महिला आयोग एक गैर-संवैधानिक/सांविधिक निकाय है।

7. राजस्थान में राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? (जेल प्रहरी P-6 2017)

(1) श्रीमती पवन सुराणा (2) श्रीमती कान्ता खतुरिया
(3) श्रीमती प्रकाशवती (4) श्रीमती तारा भण्डारी

व्याख्या—(2) आयोग के अध्यक्ष के रूप में श्रीमती कांता खतुरिया का कार्यकाल 25 मई, 1999 से 24 मई, 2002 तक रहा।

8. राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से नहीं है?

(1) महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना।
(2) महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना।
(3) महिला सशक्तीकरण हेतु प्रयास
(4) महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना।

उत्तर—(4) (कॉलेज व्याख्याता जीके- 2016)

9. राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं -

(1) तारा भण्डारी (2) पवन सुराणा
(3) ममता शर्मा (4) लाड कुमारी जैन

(PTI Grade III - 2012)(PTI II Grade-2012)(ACF- 2013)

व्याख्या—(4) राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती है, इन्होंने 11 फरवरी, 2022 को अध्यक्ष के रूप में पद संभाला।

G

लोकायुक्त

1. निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के लोकायुक्त के न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं?

- (1) राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित सेवाओं के सदस्य
(2) जिला प्रमुख (3) मंत्री (4) मुख्यमंत्री

(CET Graduation (Shift-3)-2024)

व्याख्या—(4) जो क्षेत्राधिकार लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते हैं— राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महालेखाकार, उच्च न्यायालय व जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी, मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव अधिकारी, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त, राजस्थान लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, सेवानिवृत्त लोकसेवक, विधायक, सरपंच व पंच, विधानसभा के सचिवालय स्टाफ के अधिकारी व कर्मचारी।

2. राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे?

- (1) जस्टिस आई.डी. दुआ (2) जस्टिस जे.एल. गुप्ता
(3) जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा (4) जस्टिस एस.एस. कोठारी

(राज. पुलिस— 2018) (CET Graduation (Shift-1)-2024)

(उद्योग विस्तार अधिकारी—2018) (CET 10+2 2023)

व्याख्या—(1) आई.डी. दुआ का कार्यकाल 28 अगस्त, 1973 से 27 अगस्त, 1978 तक रहा।

3. लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिये 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया?

- (1) ज्ञान प्रकाश (2) बलवंत राय मेहता
(3) प्रताप कृष्ण लोहरा (4) नरपत मल लोढ़ा

(BSTC-2024)

व्याख्या—(4) नरपतमल लोढ़ा कमेटी — राज्य सरकार ने फरवरी 2014 में मौजूदा लोकायुक्त अधिनियम के प्रावधानों को सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए श्रीनरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था।

4. राजस्थान लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति कब मिली थी?

- (1) 1983 (2) 1977 (3) 1973 (4) 1985

(VDO 28-12-2021) (Raj. Police 2024 K-1)

व्याख्या—(3) वर्ष 1973 में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अध्यादेश पारित हुआ, जो 3 फरवरी, 1973 से राजस्थान में प्रभावी हुआ। इसे 26 मार्च, 1973 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई और तब से यह अधिनियम के रूप में प्रदेश में प्रभावी है।

5. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 कब लागू किया गया था?

(Raj. Police 2024 K-2)

- (1) जनवरी 2013 (2) मई 2013
(3) दिसंबर 2013 (4) जनवरी 2014

व्याख्या—(3) पुलिस विभाग ने इसका विकल्प (3) माना है, जो गलत है। इसका सही उत्तर विकल्प (4) होगा। केन्द्रीय स्तर पर लोकपाल एवं राज्य स्तर पर लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना के लिए बहुप्रतीक्षित लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 संसद द्वारा वर्ष 2014 में पारित हुआ, जिसे 1 जनवरी, 2014 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। यह अधिनियम 16 जनवरी, 2014 से प्रभाव में आया।

6. लोकायुक्त और उपलोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है?

(Raj. Police 2024 L-1)

- (1) राज्य का राज्यपाल (2) मुख्यमंत्री
(3) लोकसभा के अध्यक्ष (4) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश

व्याख्या—(1) राजस्थान लोकयुक्त तथा उपलोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा-3 के अनुसार लोकायुक्त की नियुक्ति—राज्यपाल द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है।

चयन समिति— 1. उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
2. विपक्ष का नेता।

उप-लोकायुक्त की नियुक्ति लोकायुक्त के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है।

(स्रोत— जनक सिंह मीणा पेज नं. 201)

7. 2014 में नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है? (RAS Pre-2023)

- (1) पंचायती राज (2) मानवाधिकार
(3) राज्यपाल (4) लोकायुक्त

उत्तर—(4)

8. राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है?

- (1) मुख्य मंत्री और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
(2) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधान सभा में प्रतिपक्ष का नेता

(3) मुख्य मंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधान सभा में प्रतिपक्ष का नेता

(4) मुख्य मंत्री

उत्तर—(2)

(CET 10+2 2023)

12

प्रमुख अधिनियम

A

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की गाईड के अनुसार, निम्नलिखित में से कौनसा मूल उद्देश्य अधिनियम का नहीं है? (असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत विभाग) 2024)

- (1) नागरिकों को सशक्त करना
- (2) सरकार की कार्यवाही में पारदर्शिता और जवाबदेहिता की अभिवृद्धि
- (3) लोकतंत्र और विविधता की अभिवृद्धि
- (4) भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना

व्याख्या-(3) सूचना के अधिकार के मुख्य उद्देश्य- नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाना है।

2. आर.टी.आई. (सूचना का अधिकार) विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति किस वर्ष मिली? (LDC 1st Paper -2024)

- (1) अप्रैल 2015
- (2) जुलाई 1994
- (3) जून 2000
- (4) जून 2005

व्याख्या-(4) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को 15 जून, 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, अधिनियम के कुछ प्रावधान उसी दिन तत्काल प्रभाव से लागू हो गये थे। सम्पूर्ण रूप से यह अधिनियम भारत में 12 अक्टूबर, 2005 को लागू हुआ।

3. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए- (CET Graduation-2023)

- (i) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व लाना है।
- (ii) अरुणा राय ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसने सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त किया। सही कूट चुनिए-

- (1) कथन (i) सही है
- (2) कथन (ii) सही है
- (3) कथन (i) व (ii) सही है
- (4) कथन (i) व (ii) गलत है

उत्तर-(3)

4. निम्न में से क्या सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की बाध्यता में शामिल नहीं है? (संरक्षण अधिकारी- 2023)

- (1) अपने संगठन की विशिष्टता, कृत्यों और कर्तव्यों को 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना।
- (2) प्रकाशित सूचनाओं को हर माह अद्यतन करना।

(3) सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूची पत्रित करना जिससे इस अधिकार का उपयोग सुकर बने।

(4) सभी अभिलेखों का सुनिश्चित कम्प्यूटरीकरण।

व्याख्या-(2) धारा-4 (ए)- सभी लोक प्राधिकारियों को अधिनियम के प्रकाशन के 120 दिवसों की समयबद्ध अवधि में 17 सूत्रीय सूचनाओं का प्रकाशन करना होगा। जिसमें रिकॉर्ड्स का तैयार होना, उसका कम्प्यूटरीकरण कर नेट प्रणाली से इस प्रकार जोड़ा जाना है कि प्रत्येक नागरिक की उस तक पहुँच संभव हो।

5. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1) में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उल्लेख नहीं है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक को सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी? (संरक्षण अधिकारी- 2023)

- (1) सूचना, जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा।
- (2) किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना।
- (3) सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
- (4) सूचना, जो राज्य के विकास की प्रक्रिया को बाधित करती हो।

व्याख्या-(4) इस अधिनियम के भाग 8 के अनुसार वे सूचनाएँ निहित होती हैं जिन्हें देने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है-

1. ऐसी सूचना जिसे देने से देश की प्रभुसत्ता, अखण्डता, सुरक्षा, रणनीति, राष्ट्रीय हित को नुकसान हो तथा विदेशी संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ता हो।
2. जिससे संसद या विधानमण्डल के विशेषाधिकार भंग होते हो।
3. जिस पर न्यायालय या अन्य प्राधिकरण ने रोक लगा रखी हो।
4. जो सूचना किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त हुई हो।
5. जो पुलिस या सुरक्षा व्यवस्था को बनाये रखने के लिए विश्वास में दी गई सूचना के स्रोत को उजागर करती हो।

6. कौन-सा सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रावधान नहीं है? (स्कूल व्याख्याता लोक प्रशासन- 2015)

- (1) गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों को सूचना प्रदान करना मुफ्त है।
- (2) सूचना प्रदान करने की सीमा रेखा 45 दिन है।
- (3) आसूचना एवं सुरक्षा संगठन अधिकारी की नियुक्ति।
- (4) प्रत्येक विभाग में सूचना अधिकारी की नियुक्ति।

उत्तर-(3)